MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) In the 14th meeting of the Advisory Council on Public Distribuion System (PDS) held in July, 1992 State Governments|U.T. Administrations requested that a National Policy on PDS should be evolved so that the benefits of the PDS are restricted to to the needy and the deserving sections of the population. While this issue including the possibility of exclusion of certain categories of consumers is being examined, the current policy of the Central Government is that PDS is universal.

(b) No, Sir.

(c) The target for total foodgrain production during the end year of the Eighth Five Year Plan is 210 million tonnes. On this basis no shortfall is envisaged at present.

देश में तिलहनों का कम उत्पादन

2307. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्तामा मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेल का उत्पादन करने वाले उद्योगों का आधुनिकीकरण नहाने के कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कम खाद्य तेल तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में तथा अन्य विकासशील देशों में तिलहनों से तैयार किये जाने वाले तेल की मात्रा का आनुपातिक अन्तर कितना है ;

(ग) क्या देश में उगाये जाने वाले तिलहनों में पर्याप्त मात्रा में तेल होता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योपगपतियों द्वारा इस विषय में अनुसंधान करने और नई प्रणाली अपनाये जाने को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) देश में तिलहनों का निर्यात कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि कुछ मामलों में खानी में बकाया तेल-तत्व 14 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर हो सकता है, तथापि खनी में औसतन तेल तत्व 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के आस-पास होता है यह अन्य देशों में किए जाने वाल उत्पादन से विशेष भिन्न नहीं है ।

(ग) किसी तिलहन को तेल-तत्व मूल के रूप से जैविकीयता हैं और विभिन्न देशों में उगाए जाने हवाले तिलहनों के तेल-तत्ववों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता हैं ।

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों तथा शीष निकाय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्य को समर्थन देने के अलावा सरकार ने अनेक कदम भी उठाये हैं जैसे—परिसर में (इन हाऊस) अनुसंधान व विकास एकक स्थापित करने के लिये उदार प्रोत्साहन देना राजकोषीय प्रोत्साहन देना, जिनमें देश में अनुपलब्ध कुछ उपकरणों के लिये, जिन्हें प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिये आवश्यक समझा जाता है, आयात करने हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है, आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।